शनिवार, 22 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

जो रूट ने फील्डिंग में भी किया कमाल बने दुनिया के नंबर-1 फील्डर

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

पद्म श्री सम्मानित दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकी का 94 साल की उम्र में निधन

Page-05

राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई एफआईआर, साहिल लोचब मामले में जांच शुरू

दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब की शिकायत पर पैलेट गन फायरिंग मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई और न्यायिक जांच की मांग को लेकर धरना दिया।

दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब की शिकायत पर पेलेट गन से फायरिंग की कथित घटना के सिलसिले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में अभी तक किसी को आरोपी नहीं बनाया गया है। शिकायत पर कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका गांधी DCP ऑफिस में मौजूद थे। मामले की आगे की जांच चल रही है। जबकि राहुल गांधी ने राजधानी में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना जारी रखा। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस नेता, पीड़ित के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के छर्रों से घायल हुए 19 वर्षीय साहिल लोचब के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर शुक्रवार को संसद मार्ग स्थित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय के बाहर धरना दिया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी साहिल लोचब, उनके परिवार और वकीलों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे और मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने पुलिस से जांच अधिकारी (आईओ) का नंबर उपलब्ध कराने की मांग भी की। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आज साहिल लोचब के साथ, उनके साथ हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा।" उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई "गंभीर अपराध" है। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल न्याय के लिए प्राथमिकी दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज होगी, न्यायिक जांच होगी और "ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी।

राहुल गांधी के धरने पर जेपी नड्डा का पलटवार

बोले- यह न्याय नहीं, कैमरा दिखाने की राजनीति

दिल्ली में एक नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 21 अगस्त को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। वे 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे है। इसी को लेकर भाजपा की ओर से पलटवार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश एक बार फिर उस सस्ती और सस्ती लोकप्रियता पाने वाली राजनीति को देख रहा है, जिसका प्रदर्शन आज राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया। राहुल गांधी का आज का धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए; यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है। नड्डा ने कहा कि पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई की घटना का संज्ञान ले लिया है और एक पूर्व जज की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। जब देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले की जांच कर रही है, तो राहुल गांधी पुलिस स्टेशन के बाहर कैमरों के सामने बैठकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या विपक्ष के नेता को देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? सच तो यह है कि राहुल गांधी यह 'कैमराजीवी' नाटक सिर्फ़ खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए कर रहे हैं।

रेवंत रेड्डी की अमेरिका यात्रा को केंद्र की मंजूरी नहीं, विदेश मंत्रालय ने बताई वजह

विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की प्रस्तावित अमेरिका यात्रा को राजनीतिक मंज़ूरी नहीं दी गई, क्योंकि उनके दौरे के मक़सद के हिसाब से कार्यक्रम को उचित नहीं माना गया। सीएमओ ने शुक्रवार को पहले बताया था कि केंद्र ने रेवंत को अमेरिका जाने की इजाज़त नहीं दी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो अभी लंदन में हैं, ने अमेरिका जाने और 30 अगस्त को हैदराबाद लौटने का प्लान बनाया था। सीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया, मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले आधिकारिक 'तेलंगाना राइजिंग' प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका (U S A) की अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने यह कहते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया कि... राजनीतिक नज़रिए से मंज़ूरी नहीं दी गई है। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ़ किया कि राजनीतिक मंज़ूरी देने से पहले मंत्रालय मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं का आकलन करता है। जयसवाल ने कहा कि राजनीतिक मंज़ूरी देने के लिए विदेश मंत्रालय मुख्यमंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के मामलों का आकलन करता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रस्तावित कार्यक्रम "उनके पद और यात्रा के उद्देश्य के हिसाब से उचित" होना चाहिए। जयसवाल ने कहा इस मामले में अमेरिका की यात्रा के लिए ऐसा नहीं था, और इसलिए मंज़ूरी नहीं दी गई। हालांकि, जयसवाल ने साफ़ किया कि रेवंत की प्रस्तावित यूके यात्रा के लिए मंज़ूरी दे दी गई थी।

'वंदे मातरम' पर सियासी संग्राम तेज, अमित शाह ने कांग्रेस के 1937 के फैसले पर उठाए सवाल

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की कि उसने आज़ादी के बाद राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को पूरे दिल से नहीं अपनाया। 21 अगस्त को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए, शाह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तारीफ की, जिसमें लाल किले से 'वंदे मातरम' का पूरा गायन हुआ था। उन्होंने इस पल को अनोखा बताते हुए कहा कि 150 साल बाद और हमारी आज़ादी के 80वें साल में, देश और दुनिया ने लाल किले से 'वंदे मातरम' का पूरा गायन सुना। शाह ने इस गीत के महत्व पर ज़ोर देते हुए इसे बंकिम बाबू की एक अमर उत्कृष्ट रचना बताया, जिसने आज़ादी की लड़ाई को प्रेरित किया और आज़ाद भारत की सोच को आकार दिया। उन्होंने कहा कि इस एक गीत, इस एक साहित्यिक रचना के ज़रिए उन्होंने यह स्थापित किया कि आज़ाद भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपनाकर आगे बढ़ना चाहिए। यह दुर्भाग्यिपूर्ण है कि आज़ादी और देश के बँटवारे के बाद भी 'वंदे मातरम' को कभी पूरे दिल से नहीं अपनाया गया। गृह मंत्री ने 'राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026' को मज़बूत करने के फ़ैसले को ऐतिहासिक निर्णय भी बताया। यह कानून राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' में किसी भी तरह की बाधा डालने या उसका अपमान करने को अपराध बनाता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने संसद में एक बिल पेश किया और 'वंदे मातरम' के पूरे गायन को सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया; यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। मेरा मानना है कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि आने वाली पीढ़ियों हमारे बच्चों, किशोरों और युवाओं—तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अमर संदेश पहुँचेगा। ये बातें वंदे मातरम के गायन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहे राजनीतिक विवाद के दौरान कही गई हैं। कांग्रेस वर्किंग कमिटी ने हाल ही में 1937 के एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए घोषणा की कि पार्टी के कार्यक्रमों में इस गीत के केवल शुरुआती दो पद ही गाए जाएंगे। 20 अगस्त को अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी के 1937 के फैसले ने उन हालात को बनाने में भूमिका निभाई, जिनकी वजह से भारत का विभाजन हुआ।

मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति

वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने शुक्रवार को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। लंबे समय से सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के महासचिव रहे आलमगीर को जातीय संसद के कार्यवाहक अध्यक्ष कैसर कमाल ने बंगभवन के दरबार हॉल में पद की शपथ दिलाई। बंगभवन देश के राष्ट्राध्यक्ष का आधिकारिक कार्यालय-सह-आवास है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान, विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान, पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, कैबिनेट मंत्री, सेना के शीर्ष अधिकारी और कई अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद आलमगीर ने कैबिनेट में पांच नए सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत कुल 55 सदस्य हैं।

दिल्ली में 'आरक्षण हटाओ आंदोलन' को NOC, जंतर-मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारी

राष्ट्रीय राजधानी में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शन के खत्म होने के कुछ हफ़्तों बाद, देश भर में विरोध-प्रदर्शनों की एक लहर उठ खड़ी हुई है। इन विरोध-प्रदर्शनों के बीच, राष्ट्रीय राजधानी में "आरक्षण हटाओ आंदोलन" आयोजित किया जा रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण 'आरक्षण-विरोधी' विरोध-प्रदर्शन के लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) दे दिया है। यह घटनाक्रम "रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन" के डिजिटल कैंपेन के बीच सामने आया है। इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश की अलग-अलग हिस्सों से लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रभासाक्षी की टीम खुद वहां पहुंची थी। लगातार लोगों का वहां आना हो रहा था। अलग-अलग संगठन के लोग भी इसमें भागीदारी कर रहे हैं। यह लगातार यूजीसी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर संगठन और लोग वह है वह बीजेपी के कोर वोटर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें बीजेपी से ही उम्मीद है इसलिए हम अपनी मांग को लेकर यहां पहुंचे हैं। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरने की अनुमति नहीं दे रही है। यहां से रामलीला मैदान जाने को कह रही है। पुलिस की ओर से भी बार-बार यह कहा गया कि आप सभी को रामलीला मैदान जाना होगा। हालांकि प्रदर्शनकारी लगातार वहां जमे रहे और हजारों की संख्या में वहां पहुंचे रहे। यह इंस्टाग्राम-आधारित पेज है, जिसने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन जुटाने के तरीकों को अपनाकर तेज़ी पकड़ी है। इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन फ़ॉलोअर्स वाले इस कैंपेन ने पहले 21 अगस्त को जंतर-मंतर पर आरक्षण-विरोधी प्रदर्शन का आह्वान किया था। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी NOC के तहत, शाम 4 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था के नज़रिए से इस प्रदर्शन पर उन्हें "कोई आपत्ति नहीं" है। यह अनुमति तब मिली है जब दिल्ली पुलिस ने उन खबरों का खंडन किया था जिनमें कहा गया था कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई है।

26 साल का कार सेल्समैन निकला बेल्जियम के प्रिंस का बेटा, DNA टेस्ट ने बदली जिंदगी!

DNA टेस्ट और कानूनी मान्यता के बाद क्लेमेंट वैंडेनकेर्कहोव को आधिकारिक तौर पर प्रिंस लॉरेंट का बेटा और बेल्जियम के शाही परिवार का सदस्य माना गया है।क्लेमेंट को 16 साल की उम्र में अपने जैविक पिता के बारे में सच्चाई पता चली थी, लेकिन पिता से संपर्क करने में उन्हें कई साल लग गए।

बेल्जियम में DNA टेस्ट के बाद 26 साल के एक कार सेल्समैन की दुनिया ही पूरी तरह बदल गई। अब उसे आधिकारिक तौर पर प्रिंस लॉरेंट का बेटा और बेल्जियम के शाही परिवार का सदस्य माना गया है। यह मामला लंबे समय से छिपी रही पितृत्व की कहानी को फिर से चर्चा में ले आया है। प्रिंस लॉरेंट ने अपने बेटे क्लेमेंट वैंडेनकेर्कहोव के साथ अपने रिश्ते को करीब 6 महीने पहले एक टाउन हॉल में हुए नागरिक समारोह के दौरान कानूनी रूप से स्वीकार किया। उन्होंने सबके सामने माना कि क्लेमेंट उन्हीं का बेटा है, हालांकि इस समारोह की जानकारी हाल ही में सार्वजनिक हुई है। बेल्जियम की साप्ताहिक पत्रिका Soir Mag ने सबसे पहले इस आधिकारिक पहचान का खुलासा किया। कानूनी रूप से बेटा माने जाने के बाद क्लेमेंट को अपने पिता की संपत्ति में दूसरे बच्चों के बराबर हिस्सा मिलने की उम्मीद है। क्लेमेंट ने इस फैसले पर कहा कि वह कानूनी औपचारिकताओं को ज्यादा महत्व नहीं देता। उसके लिए सबसे बड़ी बात अपने पिता को जानने का मौका मिलना है। बता दें कि क्लेमेंट का जन्म साल 2000 में हुआ था। वह प्रिंस लॉरेंट और मॉडल-सिंगर वेंडी वान वांटेन के बेटे हैं। उनके जैविक पिता की पहचान को लेकर वर्षों तक अटकलें लगती रहीं। क्लेमेंट की शक्ल प्रिंस लॉरेंट से काफी मिलती है। इसके अलावा उनके नाम को भी लॉरेंट के टेरवुरेन स्थित आवास 'विला क्लेमेंटाइन' से जोड़कर देखा जाता रहा है। उनकी मां वेंडी ने अपने संगीत में भी इस रिश्ते को लेकर कुछ अप्रत्यक्ष संकेत दिए थे। प्रिंस लॉरेंट ने पिछले साल पहली बार सार्वजनिक तौर पर क्लेमेंट के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उस समय उन्होंने कहा था कि दोनों ने 'पिछले कुछ वर्षों में इस बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात की है।' क्लेमेंट को 16 साल की उम्र में पता चला था कि प्रिंस लॉरेंट उनके जैविक पिता हैं। हालांकि, उन्होंने उनसे तुरंत संपर्क नहीं किया। 20 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार शाही परिवार के इस सदस्य से संपर्क किया। अपने बचपन के अनुभव को याद करते हुए क्लेमेंट ने इस महीने की शुरुआत में फ्लेमिश अखबार Het Nieuwsblad से अपनी भावनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा, 'मेरा पूरा बचपन इस सवाल से जूझते हुए बीता कि मेरे पिता कौन हैं? जब मुझे सच्चाई पता चली, तो इस राज को छिपाकर रखना मेरे लिए बेहद भारी पड़ गया।' कानूनी तौर पर राजपरिवार से जुड़ने के बावजूद क्लेमेंट अपना मौजूदा पारिवारिक नाम नहीं बदलना चाहते। वह अपने पिता के शाही परिवार के नाम 'सैक्स-कोबर्ग' को अपनाने के बजाय वैंडेनकेर्कहोव ही रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, 'इस पारिवारिक नाम को छोड़ना मेरी मां ने मेरे लिए जो कुछ किया है, उसके साथ विश्वासघात होगा।' प्रिंस लॉरेंट की शादी 2003 में प्रिंसेस क्लेयर ऑफ बेल्जियम से हुई थी। दोनों के पहले से तीन बच्चे हैं। बेल्जियम के शाही परिवार में यह पहला ऐसा मामला नहीं है। वर्ष 2020 में किंग अल्बर्ट द्वितीय ने अपनी बेटी को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। वह अब प्रिंसेस डेल्फीन के नाम से जानी जाती हैं। डेल्फीन का मामला लंबे समय तक चली कानूनी लड़ाई के बाद सामने आया था। उस समय अल्बर्ट द्वितीय 2013 में बेल्जियम के सिंहासन से हट गए थे और उनके खिलाफ चल रहा पितृत्व विवाद भी बड़े सार्वजनिक विवाद में बदल गया था। क्लेमेंट की कहानी में सबसे खास बात यह है कि एक सामान्य जिंदगी जी रहा 26 वर्षीय कार सेल्समैन अब आधिकारिक तौर पर बेल्जियम के राजपरिवार का हिस्सा बन चुका है।

इमरान खान को इस्लामाबाद स्थित सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल भेज दिया गया

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को शुक्रवार सुबह सरकारी 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (पीआईएमएस) में चिकित्सा जांच के बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल वापस भेज दिया गया। चिकित्सा जांच के दौरान अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद रहे। सरकार ने यह जानकारी दी। इससे पहले दिन में, खान के अंतरराष्ट्रीय मीडिया प्रवक्ता जुल्फी बुखारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) प्रमुख इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के 'शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल' में स्थानांतरित किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के 18 अगस्त के आदेश के अनुपालन में की गई, जिसमें खान को दो दिन के भीतर अस्पताल पहुंचाने का निर्देश दिया गया था। अदालत के समक्ष पेश की गई एक चिकित्सीय रिपोर्ट में कहा गया था कि वह "लेवल थ्री प्लस एंग्जायटी" (बेचैनी, घबराहट और चिंता) की समस्या से जूझ रहे हैं। "लेवल थ्री प्लस एंग्जायटी" का मतलब है बहुत अधिक या गंभीर चिंता, बेचैनी और घबराहट होना जिसकी वजह से रोजमर्रा के काम प्रभावित होते हैं, शरीर पर बहुत अधिक तनाव पड़ता है और स्पष्ट रूप से सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है। सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने खान को शिफा अस्पताल न ले जा पाने के लिए पीटीआई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, "अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और उसके बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं की वजह से बनी सुरक्षा स्थिति को देखते हुए खान को पीआईएमएस ले जाया गया और मेडिकल जांच में वह स्वस्थ पाए गए हैं।"

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत चौपाल- 2026 का शुभारंभ किया

दिल्ली के करोल बाग से चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई

दिल्ली में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जानकारी अनुसार यहां के करोल बाग इलाके में दिनदिहाड़े एक ज्वेलरी कारोबारी की कार से शीशा तोड़कर 2 करोड़ से ज्यादा के कीमती गहने चोरी कर लिए गए। यह वारदात उस समय हुई जब कारोबारी अपने बेटे और कर्मचारी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। उस समय उनकी गाड़ी में तीन बैकपैक और एक सूटकेस था। तीनों बैग में सोने और हीरे की ज्वेलरी रखी थी। साथ में एक लैपटॉप और आधार कार्ड रखा हुआ था। जब वे खाना खाकर अपनी गाड़ी के पास आए तो उन्होंने देखा कि उनकी कार का शीशा टूटा हुआ है और उनका सारा कीमती सामान चोरी हो गया है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के जरिए आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है।जानकारी अनुसार, पीड़ित कन्हैया लाल 'SKG Kundan Crafts' नाम से आभूषण का कारोबार करते हैं। वह 18 अगस्त को अपने बेटे ध्रुव सोनी और एक स्टाफ कर्मचारी के साथ व्यापारिक मार्केटिंग के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे थे। उनके पास तीन बैकपैक और एक सूटकेस था। बैग्स में सोने व हीरे के कीमती जेवर, लैपटॉप और आधार कार्ड रखा हुआ था, जबकि एक सूटकेस में कपड़े थे। बताया जा रहा है कि 19 अगस्त को कारोबारी ने ग्रेटर कैलाश-एम ब्लॉक मार्केट में कई ज्वेलर्स से मुलाकात की। इसके बाद शाम करीब 4:00 बजे वे करोल बाग पहुंचे। शाम लगभग 5:30

बजे उन्होंने अपनी कार करोल बाग स्थित आर्य समाज रोड पर केनरा बैंक के ठीक सामने पार्क की। इसके बाद कारोबारी, उनका बेटा और कर्मचारी कार में ही सभी बैग और सूटकेस छोड़कर पास के बीकानेरवाला रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। जब वे शाम करीब 7:15 बजे वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि कार का पिछला शीशा टूटा हुआ था और कार के अंदर रखे तीनों बैकपैक और कपड़ों वाला सूटकेस गायब थे। यह देख उनके होश उड़ गए। महज एक से डेढ़ घंटे के भीतर बदमाशों ने इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे दिया और किसी को कुछ पता न चल सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के इलाकों और दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे संदिग्धों और उनकी गाड़ियों की पहचान की जा सके।

बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और दूसरे गुट लगातार पाकिस्तानी आर्मी और सरकार को निशाना बना रहे

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक बार फिर विद्रोही गुटों ने सरकारी ढांचे को निशाना बनाया है। विद्रोदी गुटों ने सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक सुविधाओं को निशाना बनाकर हमले किए हैं। एक अहम घटनाक्रम में हथियारबंद हमलावरों ने चाघी जिले के जियारत बालानोश में एक सरकारी रेस्ट हाउस में आग लगाई है। बंदूकधारी सरकारी इमारत में घुसे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, कीमती सामान लूटा और इमारत में आग लगाकर फरार हो गए। चाघी की घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हमलावरों की पहचान और नुकसान के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। चाघी की घटना बलूचिस्तान में सरकारी और सुरक्षा ठिकानों पर हो रहे हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि विद्रोही सुरक्षाबलों पर सीधे हमलों से बढ़कर प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच रहे हैं। यह जमीन पर सरकार की कमर तोड़ने जैसा है। बलूचिस्तान में चाघी से पहले पिशिन जिले के सरनान शहर में एक पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था। यहां हथियारबंद लोगों ने स्टेशन पर हमला करते हुए पुलिसकर्मियों से हथियार छीन लिए और पुलिस की गाड़ी लेकर भाग गए। सरनान में कुछ समय के लिए शहर के कई हिस्सों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। बलूचिस्तान में सैन्य काफिले पर हाल ही में एक हमले में सात सुरक्षाकर्मी मारे गए। इससे प्रांत में पाकिस्तान की सैन्य मौजूदगी के लिए बलूच अलगाववादी समूहों से बने खतरे का पता चलता है। इसी महीने, 14 अगस्त को मस्तुंग में बलूचिस्तान के गृह मंत्री मीर जियाउल्लाह लैंगोव के काफिले पर हथियारबंद हमले में वे बाल-बाल बचे हैं।

शेख हसीना ने याद किया 2004 का दर्दनाक मंजर

बांग्लादेश के इतिहास में 21 अगस्त का दिन एक बेहद दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। साल 2004 में इसी दिन ढाका में अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमला हुआ था। इस हमले में कई लोगों की जान गई थी। सैकड़ों लोग घायल हुए थे। हमले की 22वीं बरसी पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उस घटना को याद किया। उन्होंने इसे देश के इतिहास के सबसे 'क्रूर और शर्मनाक' अध्यायों में से एक बताया। उन्होंने नई पीढ़ी से इतिहास को बिना भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से समझने की अपील भी की। अवामी लीग के मुताबिक, 21 अगस्त 2004 को ढाका के 'बंगबंधु एवेन्यू' में पार्टी की रैली चल रही थी। इसी दौरान वहां ग्रेनेड से हमला किया गया। हमले में अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के 24 नेता और कार्यकर्ता मारे गए। 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई घायलों को गंभीर चोटें आईं और कुछ लोग जीवनभर के लिए अपाहिज हो गए। मृतकों में इवी रहमान भी शामिल थीं। वह उस समय महिला अवामी लीग की प्रमुख थीं। वह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान की पत्नी भी थीं। उस समय विपक्ष की नेता रहीं शेख हसीना भी हमले में बाल-बाल बची थीं। उनके कान में चोट लगी थी। हसीना के मुताबिक, उस चोट का असर आज भी है। शेख हसीना ने कहा कि इस हमले का मकसद सिर्फ नेताओं को निशाना बनाना नहीं था। उनके मुताबिक, इसके पीछे बांग्लादेश की लोकतांत्रिक राजनीति को खत्म करने की कोशिश थी। अवामी लीग ने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे तत्कालीन BNP-जमात गठबंधन सरकार से जुड़े तत्वों का हाथ था। पार्टी ने आतंकवादी संगठन हरकत-उल-जिहाद अल-इस्लामी यानी HuJI पर भी आरोप लगाया। हसीना ने अपने बयान में बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास की कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में हिंसा और टकराव का दौर पहले भी देखा गया है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को इन घटनाओं को समझना चाहिए। इतिहास को किसी एक पक्ष के नजरिए से नहीं, बल्कि निष्पक्ष तरीके से पढ़ना चाहिए। शेख हसीना ने

अपने बयान में 5 अगस्त 2024 के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी-विरोधी राजनीतिक एजेंडे से जुड़ी ताकतें फिर से सक्रिय हुई हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया।

संपादक की कलम से

लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का मौलिक दायित्व है। इसी लोकतांत्रिक अधिकार के तहत राहुल गांधी का दिल्ली के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठना एक गंभीर राजनीतिक घटनाक्रम है। पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि पुलिस कार्रवाई, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों से जुड़ा प्रश्न भी है। यदि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग को केवल राजनीति कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।दूसरी ओर, सरकार और भाजपा का यह तर्क भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है कि यदि किसी घटना की न्यायिक जांच चल रही है, तो उसके समानांतर राजनीतिक दबाव बनाने से जांच की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। लेकिन लोकतंत्र में असहमति का जवाब व्यक्तिगत आरोपों से नहीं, बल्कि तथ्यों और पारदर्शी कार्रवाई से दिया जाना चाहिए।इस पूरे विवाद का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि छात्र आंदोलन और युवाओं से जुड़े वास्तविक सवाल राजनीतिक बयानबाजी के बीच दबते जा रहे हैं। छात्रों को यह जानने का अधिकार है कि उनके साथ हुई पुलिस कार्रवाई के लिए कौन जिम्मेदार था, क्या बल प्रयोग नियमों के अनुरूप था और पैलेट गन के इस्तेमाल की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसी तरह सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों के अधिकारों तथा उनके सामने मौजूद परिस्थितियों को भी निष्पक्ष जांच में शामिल किया जाना चाहिए।विपक्ष को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन विरोध का उद्देश्य समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक टकराव बढ़ाना। सत्ता पक्ष को भी यह समझना होगा कि हर विरोध को 'ड्रामा' कह देने से जनता के सवाल खत्म नहीं होते। यदि सरकार को लगता है कि आरोप निराधार हैं, तो वह तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट करे और जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की दिशा में आगे बढ़े।आज जरूरत राहुल गांधी बनाम भाजपा की बहस से आगे बढ़कर छात्रों के वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देने की है। लोकतंत्र की ताकत इसी में है कि सड़क का विरोध, संसद की बहस और न्यायिक प्रक्रिया—तीनों एक-दूसरे के पूरक बनें। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखें और जनता के सवालों को अपनी राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनाने के बजाय उनके समाधान का माध्यम बनाएं।

महाराष्ट्र महायुति में घमासान! चंद्रकांत पाटील के कामों की जांच मांगने पर NCP पार्षद का 12 करोड़ का विकास निधि शून्य

महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी (सुनेत्रा पवार गुट) के बीच विकास निधि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।चंद्रकांत पाटील के कामों की जांच की मांग करने वाले एनसीपी पार्षद सुहास टिंगरे का करीब 12 करोड़ रुपये का विकास निधि कथित तौर पर शून्य कर दिया गया है।टिंगरे ने इसे राजनीतिक नाराजगी से जोड़ते हुए कहा कि गठबंधन अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए सवाल पूछना उनका अधिकार है।

महाराष्ट्र में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (सुनेत्रा पवार गुट) के बीच जारी खींचतान अब चरम पर पहुंच गया है। अमोल बालवडकर के बाद अब एनसीपी के नगरसेवक (पार्षद) सुहास टिंगरे का विकास निधि भी कथित तौर पर शून्य कर दिया गया है। दोनों नगरसेवकों ने भाजपा नेता और मंत्री चंद्रकांत पाटील के कामकाज का ऑडिट कराने की मांग को लेकर प्रस्ताव दिया था। इसी के बाद विकास निधि रोके जाने को लेकर सत्तारूढ़ महायुति के भीतर टेंशन बढ़ गई है। एनसीपी सुनेत्रा पवार गुट के नेता सुहास टिंगरे ने आशंका जताई है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत पाटील के कामों की जांच की मांग वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की वजह से उनका विकास निधि शून्य किया गया है। भाजपा ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुहास टिंगरे ने कहा कि एनसीपी पार्षद अमोल बालवडकर ने मंत्री चंद्रकांत पाटील के कामों की जांच कराने की मांग की थी और उन्होंने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इसके बाद उनका विकास निधि शून्य किया गया है। इस सवाल पर उन्होंने कहा, "मुझे भी यही संभावना लगती है।" टिंगरे ने कहा कि उनका किसी से व्यक्तिगत विवाद नहीं है, लेकिन अगर किसी को उनसे व्यक्तिगत नाराजगी है तो उसका खामियाजा उनके क्षेत्र के लोगों को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें मिलने वाले करीब 12 करोड़ रुपये के विकास निधि से आम लोगों के लिए काम किए जाने थे, जबकि उनके वार्ड में कई विकास कार्य अभी भी लंबित हैं। सुहास टिंगरे ने दिवंगत नेता अजित पवार का उदाहरण देते हुए कहा कि अजित पवार ने कई वर्षों तक राज्य के वित्त मंत्री के रूप में काम किया और पुणे के संरक्षक मंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में भी उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, यहां तक कि 70 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले का आरोप भी लगाया गया था। लेकिन इन आरोपों के बावजूद अजित पवार ने कभी किसी विधायक या सांसद का एक रुपया भी विकास निधि नहीं रोका। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ व्यक्तिगत नाराजगी है तो वह अलग बात है, लेकिन विकास निधि रोकने से उनके क्षेत्र के आम लोगों के विकास कार्य प्रभावित होंगे। सुहास टिंगरे ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य और केंद्र में भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन पुणे महानगरपालिका (PMC) में उनकी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। इसलिए वह विपक्ष के तौर पर सवाल उठा रहे है, जो कि स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का मतलब यह नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए उनकी पार्टी सवाल नहीं पूछ सकती। विकास कार्यों और प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाना उनका अधिकार है। गौरतलब हो कि पीएमसी में यह विवाद उस समय और गहरा गया जब उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की एनसीपी के नगरसेवक अमोल बालवडकर का विकास निधि रोक दिया गया। अब सुहास टिंगरे के निधि को भी शून्य किए जाने से महायुति के दोनों सहयोगी दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि, विकास निधि शून्य किए जाने के पीछे का आधिकारिक कारण क्या है? इसे लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दिया

उत्तराखंड में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दिया। इस दौरान ईसी पर गंभीर सवाल भी उठाए। कांग्रेस नेताओं ने 'चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ', 'चुनाव आयोग ज्ञापन लो', 'लोकतंत्र की हत्यारी ये सरकार नहीं चलेगी' और 'संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी' जैसे नारे भी लगाए। इस दौरान कुमारी सैलजा, पवन खेड़ा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपना चाहता था, लेकिन उन्हें आयोग से मुलाकात का समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पहले प्रतिनिधिमंडल को आयोग के अधिकारियों से मिलने, अपनी बात रखने और संवाद करने का अवसर मिलता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इस दौरान कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि आखिर यह कैसा लोकतंत्र है, जहां चुनाव आयोग ने अपने कार्यालय के गेट बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मामला केवल किसी एक उम्मीदवार या एक मतदाता का नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड के लोकतंत्र से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 8 लाख लोगों के वोट प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। वोटरों के नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपने प्रतीक के रूप में जंजीर और ताला अपना लेना चाहिए। खेड़ा ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग के दरवाजे जनता और उसके प्रतिनिधियों के लिए बंद होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पिछले आठ दिनों से आयोग से मिलने का समय मांग रही थी, लेकिन समय नहीं मिला, जिसके कारण नेताओं को आयोग के गेट तक आना पड़ा। वहीं उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और बिहार की तरह उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि पात्र मतदाताओं के नाम कथित तौर पर हटाए जा रहे हैं। आर्य के मुताबिक, कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई।

जंतर-मंतर के बाद थाने में राहुल गांधी का धरना पैलेट गन मामले में FIR की मांग; BJP ने बताया 'ड्रामा' और 'हठयोग'

आज से करीब एक महीने पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किया था, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, उसे लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दिल्ली में धरने पर बैठ गए हैं। छात्र आंदोलन को लेकर 21 जुलाई को भी राहुल गांधी धरने पर बैठे थे। तब वे पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे थे और आज 21 अगस्त है, जब राहुल गांधी संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि पैलेट गन मामले में FIR दर्ज की जाए। राहुल गांधी की इस धरने को लेकर BJP नेता उनके ऊपर हमलावर हैं। जानिए राहुल गांधी के थाने में धरने पर किसने क्या कहा?केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति देख रहा है। यह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और फुटेज खाने की भूख है। सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रही है लेकिन कैमरा लेकर थाने के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? नड्डा ने राहुल गांधी को कैमराजीवी बताया और कहा कि यह हताशा और हठयोग है। राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस, वंदे मातरम् पर घिर चुकी है। जनता जवाब मांग रही है। इस फजीहत से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी नया ड्रामा कर रहे हैं। संसद में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार थी लेकिन राहुल गांधी भाग खड़े हुए। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं इसलिए सड़क पर तमाशा कर रहे हैं। देश न्यायिक प्रक्रियाओं से चलता है, ऐसे हठयोग से नहीं। राहुल गांधी को जनता को जवाब देना होगा: जेपी नड्डा वहीं, BJP सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा, 'यह बहुत दुखद है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं लेकिन वे लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अराजकता की सियासत करते हैं। अभी वे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में बगैर किसी सूचना के धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी आशंका और आरोप दोनों है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम् पर जो स्टैंड लिया है, उसमें यह फंस गई है।' पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यह कुछ नया नहीं है। राहुल गांधी आज देश की पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ FIR कराने के लिए थाने में धरने पर बैठे हुए हैं। देश की सुरक्षा में लगे जवानों पर ये पहले भी सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर NCP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल बोले, 'विरोध करना हर किसी का हक है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं और लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। जहां तक युवाओं और उनसे जुड़े मसलों की बात है, PM मोदी इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और संवेदनशील भी हैं।

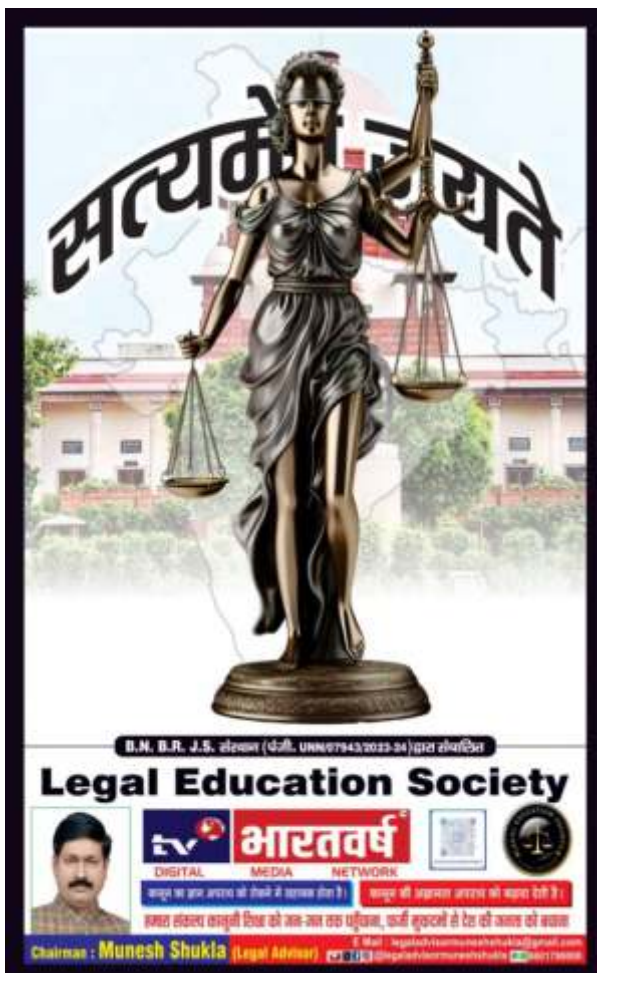

DU का बड़ा फैसला: अब MA के बिना भी कर सकेंगे PhD, 4 साल की UG डिग्री और 7.5 CGPA जरूरी

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने अब बिना मास्टर्स डिग्री (M A) भी पीएचडी एडमिशन लेने का रास्ता खोल दिया है। डीयू ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत अपने चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को सीधे पीएचडी की पढ़ाई शुरू करने का मौका दिया है। स्टूडेंट्स अपना FYUP पूरा करने के बाद सीधे पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

डीयू द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, यह मौका सिर्फ उन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, जिन्होंने 'अंडरग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022' (U G C F) के जरिए, 2022-23 एकेडमिक सेशन से चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम (FYUP) में एडमिशन लिया था। हालांकि, बिना एमए डिग्री के पीएचडी एडमिशन के लिए नंबरों की शर्त भी रखी गई है। एकेडमिक काउंसलि और एग्जीक्यूटिव काउंसलि की मंजूरी के बाद, यूनिवर्सिटी ने ऑर्डिनेंस VI में बदलाव किया है। 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए P h D एडमिशन में चार वर्षीय यूजी डिग्री में प्राप्त नंबरों का शर्त बनाया है। जो स्टूडेंट्स 7.5 CGPA नंबर लाकर FYUP चार वर्षीय प्रोग्राम पूरा करेंगे, वे सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं आरक्षित वर्ग (SC/ST) के छात्रों को 5% की छूट दी गई है। उन्हें 7 CGPA लाना होगा। डीयू का कहना है कि यूनिवर्सिटी अपने रिटायर्ड प्रोफेसर की इस बात से सहमत है कि FYUP पूरा करने वाले छात्रों के लिए मास्टर प्रोग्राम करना जरूरी नहीं है, और यूनिवर्सिटी ने इसके लिए जरूरी रास्ता पहले ही बना दिया है। डीयू ने 21 अगस्त 2026 को एक नोटिस जारी कर 4 वर्षीय अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स की संख्या, सीटों की संख्या, पीजी एडमिशन आदि को लेकर अहम जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी ने बताया कि एकेडमिक सेशन 2022-23 में चार वर्षीय यूजी डिग्री के पहले बैच में कुल 75,948 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। हालांकि 40,005 स्टूडेंट्स 2025 में अपने थर्ड ईयर में बाहर निकल गए और लगभग 35,943 स्टूडेंट्स ने चार साल की ऑप्शनल यूजी डिग्री की पढ़ाई पूरी की। इसमें ओपन लर्निंग वाले स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। डीयू ने दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले कई ज्यादा पीजी सीटें ऑफर की थीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 'पोस्टग्रेजुएट करियर फ्रेमवर्क 2025' (PGDC) के तहत पीजी लेवल के 46 प्रोग्राम में कुल 5,857 सीटें ऑफर की गई थीं। इनमें 2,807 सीटें रेगुलर मोड में और 3,035 सीटें ओपन डिस्टेंस लर्निंग (O D L) की थीं। इसके मुकाबले जेएनयू ने 4 प्रोग्राम में 71 सीटें और AUD ने 7 प्रोग्राम में 210 सीटें ऑफर की थीं।

इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आपको यूएनडीपी में यह अपॉर्चुनिटी मिल रही है

इंटर्नशिप करना चाहते हैं? तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (U N D P) ने इंटर्नशिप निकाली है। जिसके जरिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स को यहां काम करने का चांस दिया जा रहा है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अच्छी जगह इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, वो यहां अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। यूएनडीपी की यह इंटर्नशिप डिजिटल, एआई एंड इनवोशन पर आधारित पर है। तीन महीने की अवधि के दौरान कैंडिडेट्स इसी फील्ड से जुड़े अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। सबसे खास बात कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यह फुल टाइम इंटर्नशिप होम बेस्ड है। यानी आप घर से भी इस इंटर्नशिप का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपने अभी-अभी कॉलेज पास किया है, तो इस इंटर्नशिप में पैसे भी कमा पाएंगे। क्योंकि यह पेड है। हर महीने कैंडिडेट्स को स्टाइपेंड मिलेगा। कैंडिडेट ग्रेजुएट स्कूल प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहो हो।

फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम (अंडरग्रेजुए-बैचरर या उसके बराबर) कोर्स के फाइनल एकेडमिक ईयर में एनरोल हों।

यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ ग्रेजुएट हों। अगर सेलेक्ट होते हैं, तो एक साल के अंदर इंटर्नशिप शुरू करनी होगी।

वर्कस्ट्रीम के जितने भी फील्ड हैं, उनमें से किसी एक में दिलचस्पी या अनुभव है, तो बेहतर है।

इंटर्न की पोस्ट पर चयनित होने के बाद कैंडिडेट के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आएंगी, जिनपर उन्हें काम करना होगा।

सिस्टम में बदलाव, इनोवेशन और नई पॉलिसी अप्रोच पर रिसर्च करें और एनालिटिकल कंटेंट तैयार करना।

पॉलिसी इनोवेशन और सिस्टम बदलाव से जुड़े ग्लोबल और रीजनल ट्रेंड्स की पहचानना और समझना।

इनोवेटिव पॉलिसी और प्रोग्राम अप्रोच को डिजाइन करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना और उन्हें बेहतर बनाने पर काम करना।

सिस्टम में बदलाव लाने के लिए इनोवेटिव पॉलिसी और प्रोग्राम अप्रोच को डिजाइन करना, टेस्ट करना और उनका डॉक्यूमेंटेशन करना।

त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए एक पदक पक्का कर लिया

कोच कुलदीप यादव का बचाव करते हुए कहा बहुतुले ने कहा, 'कुलदीप शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं

भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच साइराज बहुतुले ने कुलदीप यादव का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि बाएं हाथ का यह कलाई का स्पिनर टीम मैनेजमेंट की योजनाओं का हिस्सा है और एक मैच में खराब प्रदर्शन से उनकी काबिलियत तय नहीं होती। पहले टेस्ट में कुलदीप को दोनों पारियों में कुल 25 ओवर गेंदबाजी करने के बाद सिर्फ एक विकेट मिला था। दूसरी ओर बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार और अनुभवी रविंद्र जडेजा ने मिलकर 14 विकेट लिए थे। बहुतुले ने कहा, 'कुलदीप शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। गॉल में परिस्थितियां अलग थीं। उन्हें एक अलग भूमिका निभानी पड़ी। कुलदीप हमेशा से मैच जिताने वाले गेंदबाज रहे हैं और टीम की योजना में शामिल हैं।' बहुतुले ने कहा, 'सभी स्पिनरों को नरम गेंद से परेशानी होती है। लेकिन बाएं हाथ के स्पिनर या ऑफ स्पिनर उंगलियों से गेंद को नियंत्रित कर लेते हैं इसलिए उनके लिए यह थोड़ा आसान होता है। वहीं, लेग स्पिनर के लिए नरम गेंद से गेंदबाजी करना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि गेंद की सीम दबकर नीचे चली जाती है।' बहुतुले ने कहा, 'एक मैच के प्रदर्शन से किसी गेंदबाज का आकलन नहीं किया जा सकता। कुलदीप ने भी परिस्थितियों के मुताबिक अपनी भूमिका में बदलाव करने की पूरी कोशिश की।' गॉल की पिच और कूकाबुरा गेंद की स्थिति ने भी कुलदीप को अपनी गेंदबाजी की दिशा और गति में बदलाव करने के लिए मजबूर किया। गेंद की शुरुआती चमक खत्म होने के बाद वह नरम हो गई थी। मानव सुथार ने गॉल टेस्ट में 10 विकेट लेकर अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। उनकी गेंदबाजी से बहुतुले काफी प्रभावित नजर आए। बहुतुले ने कहा, 'सुथार अब टीम के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी बनते जा रहे हैं।

जो रूट ने फील्डिंग में भी किया कमाल बने दुनिया के नंबर-1 फील्डर

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम अपनी पहली में सिर्फ 171 रनों पर ढेर हो गई। इसके जवाब में इंग्लिश टीम ने 409 रन बनाते हुए पहली पारी के आधार पर 238 रन की बढ़ हासिल की। फिलहाल तीसरे दिन लंच ब्रेक तक पाकिस्तानी टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 59 रन बनाए हैं। वह अभी भी 179 रन पीछे है। यहां से उस पर पारी से हार का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं, इंग्लैंड की ओर से पहली पारी में 66 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेलने वाले जो रूट ने फील्डिंग में भी एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। बता दें कि पाकिस्तान की दूसरी पारी से पहले जो रूट के नाम टेस्ट क्रिकेट में 218 कैच दर्ज थे और वह ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी स्टीव स्मिथ 218 कैच के साथ बराबरी पर थे। पाकिस्तान की दूसरी पारी में अजान अवैस का कैच लेते ही वह सबसे ज्यादा टेस्ट कैच लेने वाले दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट में बल्ले के बाद फील्डिंग में भी जो रूट ने एक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। पाकिस्तान की दूसरी पारी में अजान अवैस का कैच लेते ही वह स्टीव स्मिथ को पछाड़ दुनिया के सबसे ज्यादा कैच लेने वाले दुनिया के नंबर-1 फील्डर बन गए।

पाकिस्तानी फील्डिंग का एक और नमूना

इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के दूसरे दिन एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसने मैदान पर मौजूद दर्शकों को लोटपोट कर दिया। पाकिस्तान टीम की मैदान पर ढिलाई और समझदारी की कमी एक बार फिर जगजाहिर हो गई। एक आसान से रन आउट के मौके को हाथ से गंवाकर मेहमान टीम ने न सिर्फ मौका गंवाया बल्कि मैदान पर एक मजाकिया स्थिति भी पैदा कर दी। ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब इंग्लैंड के बल्लेबाज डैन लॉरेंस ने कदम आगे बढ़ाकर पाकिस्तान के गेंदबाज की फुलटॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बॉल सीधे पैड पर जाकर लगी और पूरी पाकिस्तानी टीम जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील में डूब गई। स्लिप में खड़े कप्तान सलमान अली आगा और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान इतने उत्साह में आ गए कि वे अंपायर की तरफ देखकर चिल्लाने लगे। इस शोर-शराबे और अपील के चक्कर में दोनों ही खिलाड़ी यह भूल गए कि लॉरेंस क्रीज से काफी बाहर खड़े थे और उनके पास रन आउट करने का

सुनहरा मौका था। बल्लेबाज को जब एहसास हुआ कि वह खतरे में है तो उसने पीछे मुड़कर वापस अपनी क्रीज में बल्ला टिकाने की कोशिश की। इसी दौरान कप्तान आगा को अचानक ख्याल आया कि स्टंप्स उखाड़ने का मौका है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आगा ने जैसे ही थ्रो मारना चाहा अपील में पूरी तरह मशगूल विकेटकीपर रिजवान खुद थ्रो के रास्ते में आ गए। नतीजा यह हुआ कि थ्रो थ्रो विकेट पर लगने की बजाय रिजवान से टकरा गया और लॉरेंस ने सुरक्षित रूप से क्रीज में कदम रख लिया। बाद में पाकिस्तान ने एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू भी लिया लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिला। पाकिस्तान के लिए यह चूक बेहद भारी साबित हुई। जीवनदान का फायदा उठाते हुए लॉरेंस ने शानदार अर्धशतक जड़ दिया और इंग्लैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। मेजबान इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 366 रन बनाकर 195 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली जबकि पाकिस्तान की पहली पारी महज 171 रनों पर ढेर हो गई थी।

दुबई में स्कूल फीस 14 लाख, बस का खर्च 3 लाख

दुबई में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी की स्कूल की पढ़ाई पर होने वाले सालभर के खर्च का पूरा हिसाब सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस खर्च को देखकर कई लोग हैरान हैं. महिला के मुताबिक, बेटी की सिर्फ सालाना ट्यूशन फीस करीब 14 लाख रुपये है. इसके अलावा स्कूल बस, यूनिफॉर्म और दूसरी सुविधाओं के लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं. इस पूरे खर्च की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दुबई में पढ़ाई की बढ़ती लागत को लेकर चर्चा कर रहे हैं.

अरुणाचल की बच्ची का वीडियो वायरल, कहा- हमें चाइनीज मत बोलो, हम इंडियन हैं

शक्ल देखकर तय न करें राष्ट्रीयता

अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में जब उससे पूछा गया कि क्या वह चीनी है, तो बच्ची ने बेहद मासूम लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा कि वह भारतीय है और उसे 'इंडियन' कहा जाए.

सोशल मीडिया पर इन दिनों अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी बच्ची का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक व्यक्ति बच्ची से पूछता है कि क्या वह चीनी है.

इस सवाल पर बच्ची मासूम अंदाज में अपनी बात रखती है. वह कहती है कि वह और उसके जैसे लोग भारतीय हैं और उन्हें चीनी कहे जाने पर गुस्सा

भी आता है और दुख भी होता है. वीडियो में बच्ची बेहद आत्मविश्वास के साथ कहती है- हम लोग इंडियन हैं. आप हमको चाइनीज बोलने से बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं. हमको इंडियन बोलो. इसके बाद वह यह भी बताती है कि वह भारत के अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है और इटानगर में रहती है. बच्ची की उम्र भले ही कम है, लेकिन अपनी पहचान को लेकर उसकी बात बिल्कुल साफ है. उसने किसी से लड़ाई नहीं की और न ही ऊंची आवाज में बात की. उसने बस इतना समझाया कि किसी को उसके चेहरे या शक्ल-सूरत के आधार पर दूसरे देश का नागरिक मान लेना सही नहीं है. इस बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई लोगों ने बच्ची के जवाब की तारीफ की है. लोगों का कहना है कि इतनी छोटी उम्र में बच्ची ने जिस तरह अपनी बात रखी, वह काफी समझदारी वाली बात है. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि किसी भारतीय नागरिक को बार-बार यह बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वह भारतीय है. बच्ची के जवाब ने लोगों का ध्यान उस समस्या की ओर खींचा है, जिसका सामना नॉर्थ-ईस्ट भारत के कई लोगों को करना पड़ता है.

लोगों ने बच्ची की हिम्मत को सराहा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने बच्ची के आत्मविश्वास की तारीफ की. लोगों को उसका मासूम लेकिन मजबूत जवाब पसंद आया. कई लोगों ने कहा कि बच्ची ने बहुत छोटी उम्र में एक बड़ी बात समझा दी है- भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को उसकी शक्ल-सूरत से नहीं, बल्कि उसकी पहचान और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए. अरुणाचल प्रदेश की इस बच्ची का छोटा सा जवाब अब सोशल मीडिया पर एक बड़े संदेश की तरह देखा जा रहा है. उसकी बात में नाराजगी जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पहचान पर गर्व है. वह बस इतना चाहती है कि लोग उसे किसी दूसरे देश से जोड़कर न देखें, बल्कि उसी तरह पहचानें जैसी वह है- एक भारतीय.

ऐसा क्यों कर रहे लोग?

चीन में बढ़ा 'चेहरा किराए पर' देने का ट्रेंड

चीन में लोग AI कंपनियों को अपना चेहरा और आवाज़ किराए पर देकर हर महीने 1,400 से 67,000 रुपये तक कमा रहे हैं. कंपनियां इन डिजिटल चेहरों का इस्तेमाल विज्ञापनों, लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया कंटेंट में कर रही हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल ने कमाई के नए रास्ते खोल दिए हैं. अब चीन में कई लोग अपना चेहरा और आवाज एआई कंपनियों को किराए पर देकर अच्छी कमाई कर रहे हैं. इसके बदले उन्हें हर महीने करीब 1,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये तक मिल रहे हैं. हालांकि, इस आसान कमाई के पीछे कई ऐसे खतरे भी छिपे हैं जो

भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकते हैं.

दरअसल, चीन में कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां लोग अपनी तस्वीरें, वीडियो और आवाज़ अपलोड करके एआई कंपनियों को इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं. इसके बाद एआई तकनीक उनकी शक्ल और आवाज की हूबहू डिजिटल कॉपी तैयार कर लेती है. इस डिजिटल चेहरे का इस्तेमाल विज्ञापनों, सोशल मीडिया वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन प्रमोशन और दूसरे डिजिटल कंटेंट बनाने में किया जाता है. जो लोग अपना चेहरा AI को किराए पर देते हैं, उन्हें एक तय रकम दी जाती है. कुछ लोगों को एक बार पेमेंट मिलता है, जबकि कई मामलों में हर महीने पैसे दिए जाते हैं. कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि उनका चेहरा कितनी बार और किस तरह के कंटेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है.

क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

अगर कोई व्यक्ति एआई के लिए अपना चेहरा या आवाज़ देने का फैसला करता है, तो उसे पहले कंपनी की विश्वसनीयता जरूर जांचनी चाहिए. किसी भी डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट को बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए. यह भी समझना जरूरी है कि कंपनी आपके डेटा का इस्तेमाल कितने समय तक और किन-किन उद्देश्यों के लिए करेगी. साथ ही यह भी देखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर क्या आप अपनी अनुमति वापस ले सकते हैं या नहीं. यदि इन बातों का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तो ऐसे ऑफर से दूरी बनाना ही बेहतर है.

महिला ने रेपिडो पर किया 20 लाख का केस!

बेंगलुरु में रैपिडो बाइक टैक्सी से ऑफिस जा रही एक महिला की जिंदगी कुछ ही मिनटों में बदल गई. महिला का आरोप है कि बाइक चालक की लापरवाही की वजह से उसका ग एक्सीडेंट हो गया. इस वजह से उसे कई बड़ी सर्जरी करानी पड़ी. इलाज पर 20 लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो गए. अब महिला ने रैपिडो पर साथ न देने का आरोप लगाते हुए कंज्यूमर कोर्ट जाने का फैसला किया है.

400 से ज्यादा फिल्मों में किया था अभिनय

पद्म श्री सम्मानित दिग्गज अभिनेत्री सौकार जानकी का 94 साल की उम्र में निधन

पद्म श्री से सम्मानित सौकार जानकी का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल के ICU में इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। वह कुछ समय से सांस लेने में तकलीफ और बुढ़ापे से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही थी। हाल ही में उनकी तबीयत फिर से बहुत बिगड़ गई और परिवार वाले उन्हें चेन्नई के कावेरी अस्पताल ले गए, जहां उनका निधन हो गया। नादिगर संगम के प्रेसिडेंट नासर ने भी इस दुख खबर की पुष्टि की है। हाल ही में एक्टर कयाल देवराज ने सोशल मीडिया पर सौकार जानकी के अस्पताल में भर्ती होने की खबर शेयर की थी और उनकी सेहत के बारे में जानकारी दी थी। 1950 में सौकार जानकी ने LV प्रसाद की डायरेक्ट की हुई तेलुगु फिल्म 'शावुकारु' से सिनेमा में डेब्यू किया। उन्होंने 1952 में TR सुंदरम की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'वलयापति' से तमिल सिनेमा में कदम रखा। इतने सालों में जानकी ने अपने करियर में तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। 1959 में उन्होंने कन्नड़ सिनेमा की पहली पैन-इंडिया फिल्म 'महिषासुर मर्दिनी' में डॉ. राजकुमार के साथ काम किया। मलयालम सिनेमा में उन्होंने 1964 की फिल्म 'स्कूल मास्टर' से डेब्यू किया। जानकी ने 1991 में दूरदर्शन के तमिल शो 'ऊरारिंदा रहस्यम' से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। सौकार जानकी ने तेलुगु, मलयालम, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 400 से ज्यादा फिल्मों और एक मलयालम फिल्म में काम किया। वह अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही। भारत सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। सौकार जानकी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था, जिसमें 'वडुंते डब्बा', 'कन्या शुल्कम', 'पिच्ची पुलैया', 'रेचुक्का-पगतीचुक्का', 'रोजुलु मरायी', 'सोंथवूर', 'जयम मनदे', 'डॉक्टर चक्रवर्ती', 'संसारम ओका चदरंगम', 'टोडिकोडल्लू', 'बाबू बंगाराम', 'गीतांजलि' जैसी कई हिट मूवीज शामिल है। आखिरी बार उन्हें 'अन्नी मांची सकुनमुले' में देखा गया था। आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में एक कन्नड़ भाषी परिवार में जन्मीं सौकार जानकी, जिनका जन्म का नाम शंकरमंची जानकी था। उनकी शादी उनके परिवार ने कम उम्र में ही कर दी थी। वह आकाशवाणी मद्रास ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो जॉकी के तौर पर काम करती थीं। 1947 में उनकी शादी शंकरमंची श्रीनिवास राव से हुई। उन्होंने गर्भवती होने के दौरान ही अपनी मैट्रिक की परीक्षा दी और बाद में असम की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। उनकी दो बेटियां और एक बेटा है - यज्ञ प्रभा कोटी, वेंकटरमण शंकरमंची और साची राव। वहीं सौकार की छोटी बहन कृष्णा कुमारी और पोती वैष्णवी अरविंद ने भी उन्हीं के नक्शेकदम पर चलते हुए एक्टिंग को अपना करियर बनाया।

लखनऊ में अतिक्रमण से परेशान 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने CM योगी से लगाई गुहार

सीतापुर रोड के पुरनिया तिराहे पर सड़क और फुटपाथ पर अवैध कब्जे से परेशान बुजुर्ग महिला ने वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और सुरक्षा की मांग की है।महिला का आरोप है कि विरोध करने पर दुकानदार धमकी देते हैं और परिवार के आने-जाने में भी परेशानी होती है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलग-अलग चौराहों पर फल सब्जी विक्रेताओं की ओर से अवैध कब्जा करने से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला नया मामला मड़ियांव थाना क्षेत्र से सामने आया है। लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित पुरनिया तिराहा पर सड़क और फुटपाथ पर जमे अवैध फल-सब्जी विक्रेताओं की अराजकता और गुंडई से तंग आकर एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। मड़ियांव इलाके की रहने वाली बुजुर्ग पीड़िता रामेश्वरी पांडेय ने आरोप लगाया है कि मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से 40 से 50 दुकानें लगाकर कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते न केवल स्थानीय निवासियों का पैदल चलना दूभर हो गया है, बल्कि विरोध करने पर ये असामाजिक तत्व धारदार हथियार दिखाकर खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बुजुर्ग पीड़िता ने जारी हुए वीडियो में बताया कि वह 1985 से पुरनिया तिराहे के पास बने अपने मकान पांडेय सदन में सपरिवार रह रही हैं। बीते कुछ वर्षों से परवेज फल की दुकान समेत दर्जनों विक्रेताओं ने उनके घर के सामने फुटपाथ और मुख्य सड़क पर अवैध कब्जा जमा लिया है। इन दुकानों पर आने वाले ग्राहक मुख्य गेट के सामने ही आड़े-तिरछे वाहन पार्क कर घंटों गायब रहते हैं, जिससे आपात स्थिति में निकलना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बुजुर्ग पीड़िता ने आरोप लगाया कि परिवार की महिलाओं और बहू-बेटियों के बाहर निकलने पर दुकानदार अभद्र फब्तियां कसते हैं और विरोध करने पर 20-25 लोगों का झुंड बनाकर गाली-गलौज व मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। बुजुर्ग महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनके बेटे इस अराजकता का विरोध करते हैं तो ये दुकानदार अपनी दुकानों व ठेलों पर रखे बड़े चाकू और छुरियां दिखाकर धमकाने लगते हैं। उपद्रवी यहां तक कह देते हैं कि 'चाहे पुलिस के पास जाओ, नगर निगम जाओ या योगी आदित्यनाथ के पास, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा।' पीड़िता का कहना है कि बरसात के दिनों में घर के सामने भारी जलभराव और कीचड़ हो जाता है, जिससे फिसलकर गिरने और चोटिल होने का गंभीर खतरा बना रहता है।पीड़ित महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन और लखनऊ नगर निगम में कई बार लिखित और मौखिक शिकायतें की गईं। लेकिन अब तक कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रही धमकियों और असुरक्षा के माहौल से त्रस्त होकर बुजुर्ग महिला ने वीडियो जारी करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तुरंत हस्तक्षेप करने, फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटवाने और दबंग तत्वों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई कर परिवार को सुरक्षा दिलाने की पुरजोर मांग की है।

बैंक कर्मचारी महिला की उसके पति ने गोली मारकर हत्या कर दी

लखनऊ के गोमतीनगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिट विभाग में कार्यरत मानस बाजपेयी (38) ने आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर पत्नी दिव्या मिश्रा (35) की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी हुसड़िया चौराहा स्थित घर पहुंचा और कमरे में मौजूद बहन तूलिका (28) की हत्या की और फिर खुद भी गोली मारकर जान दे दी।तीनों घटनाएं 30 मिनट के भीतर हुईं। गोली मारकर हत्या करने के बाद व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया। इसमें लिखा, आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद और बहन को मारना होगा... पत्नी की बहन प्रज्ञा और भरत सब जानते हैं। मानस ने बहन की सुरक्षा के लिए बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। पुलिस ने डीवीआर को कब्जे में ले लिया है। पूरी घटना कैमरे में कैद है। ममेरे भाई अंशु मिश्र के मुताबिक, वाट्स एप स्टेटस देखने के बाद उन्हें घटना की जानकारी हुई। जानकीपुरम स्थित बैंक में कार्यरत मानस पिछले तीन माह से ऑडिट के सिलसिले में बाहर थे दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्र यूट्यूबर हैं। उन्होंने बताया कि मेरी बहन दिव्या पति की साइको हरकतों और उसकी बहन के पागलपन की बीमारी की वजह से अलग रह रही थी। नवंबर 2025 के बाद दिव्या मानस के घर नहीं गई थीं।

रोज की तरह वो सुबह नौ बजे दफ्तर पहुंची थी और फिर कुछ चेक कलेक्ट करने के लिए अपने सहयोगी के साथ बाहर चली गईं। इस बीच उसका साइको पति दो रिवॉल्वर के साथ ऑटो से रेकी करने लगा। जब दिव्या बैंक पहुंची तो गेट पर उसके पति ने पहले असलहे से गोली चलाई।

रक्षाबंधन से पहले लखनऊ में मिठाई की दुकान पर बड़ा छापा 1675 किलो मिठाई नष्ट1000 लीटर घोल में मिलीं मरी मक्खियां

रक्षाबंधन से पहले लखनऊ के काकोरी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरदोईया लालनगर स्थित शिवाच्छी स्वीट्स पर छापा मारा। यहां मिठाई बनाने की जगह के आसपास 40-50 भैंसें बंधी मिलीं। गंदगी के बीच तैयार मिठाइयों पर मक्खियां और दूसरे कीड़े घूम रहे थे। करीब 1000 लीटर घोल में मरी हुई मक्खियां मिलने पर टीम ने 1675 किलो मिठाई और घोल नष्ट कराया। 15 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 20 अगस्त को दुकान की जांच की। संचालक संजीत कुमार की मौजूदगी में पता चला कि प्रतिष्ठान के पास खुदरा श्रेणी का लाइसेंस है, जबकि यहां बड़े स्तर पर मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। निर्माण स्थल पर सफाई की हालत भी खराब मिली। दीवारों पर प्लास्टर नहीं था और पास की खुली नाली में गंदा पानी जमा था। टीम को गंदे प्लास्टिक ड्रमों में स्किम्ड मिल्क पाउडर, चीनी और पानी से तैयार करीब 1000 लीटर घोल मिला। इसमें कई मक्खियां गिरी थीं, कुछ मरी हुई भी थीं। मौके पर 1675 किलो तैयार मिठाई मिली। इसमें 1000 किलो कलाकंद, 300 किलो डोडा बर्फी, 350 किलो चिकनी बर्फी और 25 किलो पेड़ा शामिल था। जांच में सामने आया कि दुकान पर काम करने वाले करीब 25 कर्मचारियों का हेल्थ टेस्ट नहीं कराया गया था। वे हेड कवर, एप्रन और ग्लव्स का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। पेस्ट कंट्रोल और इस्तेमाल होने वाले पानी की जांच की व्यवस्था भी नहीं मिली। टीम ने 686 किलो खाद्य सामग्री जब्त कर ली। इसकी कीमत करीब 79,170 रुपए बताई गई है। इसमें मिल्क पाउडर, सूजी, फिटकरी, काजू, मूंगफली, बूंदी और सफेद दानेदार पाउडर शामिल हैं। इसके अलावा 2675 किलो खराब खाद्य सामग्री, जिसकी कीमत करीब 2.77 लाख रुपए है, नष्ट करने के लिए अलग रखी गई। देर रात होने के कारण इसे मौके पर नष्ट नहीं किया जा सका। पूरा सामान एक कमरे में रखकर उसे सील कर दिया गया।

मुख्यमंत्री आवास पर जापानी छात्रों से मुलाकात की और उन्हें भारतीय दर्शन से परिचित कराया

मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसमें कूटनीति की औपचारिकता की जगह बच्चों की मुस्कान थी, भाषाओं की दूरी की जगह संवाद था और दो देशों की संस्कृति के बीच दोस्ती का एक सहज सेतु बनता दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश-जापान निवेश बैठक के क्रम में आयोजित विशेष कार्यक्रम 'ए डायलॉग विद द फ्यूचर' में जापान के यामानाशी प्रान्त से आए 13 विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी प्रान्त के गवर्नर कोटारो नागासाकी की मौजूदगी में हुआ यह संवाद आने वाले भारत-जापान संबंधों की उस तस्वीर को सामने ला रहा था, जिसकी नींव आज की युवा पीढ़ी के मन में रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने जापान के यामानाशी से आए विद्यार्थियों और उनके फैकल्टी सदस्यों तथा लखनऊ के युवा साथियों का आत्मीय स्वागत करते हुए जापानी अभिवादन 'ओहायो गोजाइमासु' से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र है और इसे 'हार्टलैंड ऑफ इंडिया' के रूप में भी देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल विद्यार्थियों का मिलन नहीं है। यह दो संस्कृतियों, दो परंपराओं और दो देशों की युवा पीढ़ियों का मिलन है। अगले वर्ष भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे समय में दोनों देशों के ये विद्यार्थी भविष्य के राजदूत के रूप में इस संबंध को नई ऊंचाई देने की क्षमता रखते हैं।

लखनऊ में गरज-चमक के साथ दिन में बादलों की आवाजाही रही झमाझम बारिश

लखनऊ में गरज-चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है। गुरुवार को दिन में बादलों की आवाजाही रही। शाम करीब 5 बजे सरोजनीनगर में बारिश शुरू हो गई। इसके बाद गोमती नगर, महानगर, हुसैनगंज, हजरतगंज में तेज बारिश होने लगी। हुसैनगंज में करीब 30 मिनट तेज बारिश की वजह से घरों और दुकानों में पानी भर गया। मरीन ड्राइव और शहीदपथ से वीवीआईपी चौराहे तक कानपुर रोड पर जलभराव हो गया। अभी तक मानसून के दौरान लखनऊ में सामान्य से 14 फीसदी कम बरसात दर्ज की गई है। बुधवार को 15.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दिन सामान्य बारिश का औसत 9.6 मिलीमीटर है। यह सामान्य से 61 फीसदी अधिक रहा है। वहीं, मानसून में अभी तक 391.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। जबकि सामान्य बारिश का औसत 456.5 मिलीमीटर रहा है। हुसैनगंज में करीब 30 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे कई घरों व दुकानों में पानी भर गया। गोमतीनगर के विशाल खंड में दिन में धूप निकली थी। शाम को घने बादल छा गए। उसके बाद बारिश शुरू हो गई।

निषाद समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर, संजय निषाद ने भाजपा से जवाबदेही तय करने को कहा

उत्तर प्रदेशसरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने निषाद समुदाय को आरक्षण देने की मांग को लेकर एक बार फिर अपनी बात मजबूती से रखी है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का वादा भाजपा के एजेंडे का हिस्सा रहा है और अब इस मुद्दे पर जवाबदेही भी भाजपा की है। वहीं, भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के प्रमुख की नाराजगी पर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक मंच के बजाय कैबिनेट और एनडीए की बैठकों में उठाया जाना चाहिए। निषाद समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर संजय निषाद ने कहा कि इस सवाल का जवाब भाजपा से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षण का वादा भाजपा ने खुद किया था और यह उसके एजेंडे का हिस्सा रहा है। संजय निषाद ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी, तब पार्टी इस मुद्दे की वकालत करती थी। अब जब भाजपा सत्ता में है और सरकार चला रही है, तो इस मामले में उसकी जवाबदेही बनती है। संजय निषाद ने अपनी भूमिका को लेकर कहा कि वह वकील हैं और अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर वकालत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि निषाद समाज ने उन्हें ताकत और जिम्मेदारी दी है और समुदाय के भरोसे के कारण वह लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने 14 किताबें लिखी हैं और 'दलील दल' का गठन भी किया है। उनका कहना है कि वह ठोस तर्कों के आधार पर अपनी बात रखते हैं और इसी तरह आगे भी समुदाय से जुड़े मुद्दों को उठाते रहेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए संजय निषाद ने उन लोगों पर भी निशाना साधा, जिन पर उन्होंने समुदाय के हितों के बजाय राजनीतिक या निजी फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग ठोस तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, वही सही मायने में अपने पक्ष की वकालत करते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग विरोधी दलों से पैसे लेकर समुदाय के बीच बांटने का काम करते हैं। हालांकि, उनके इस दावे पर संबंधित पक्षों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। संजय निषाद की आरक्षण को लेकर सार्वजनिक नाराजगी पर यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संजय निषाद एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी और बड़े नेता हैं। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि आरक्षण की मांग करना पूरी तरह उचित है, लेकिन सरकार के भीतर ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए उचित मंच मौजूद हैं। उनके मुताबिक, कैबिनेट की बैठकें लगभग हर सप्ताह होती हैं और एनडीए की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

छह माह की ट्रेनिंग के बाद कानपुर-उन्नाव की फैक्ट्रियों में रोजगार का प्रयास

18 से 35 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण का लाभ

उन्नाव में लखनऊ-कानपुर नेशनल हाईवे स्थित बंथर के पास एक चमड़ा फैक्ट्री परिसर में शुक्रवार दोपहर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भगवंतनगर विधायक आशुतोष शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कुशल बनाकर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रशिक्षण केंद्र के निदेशक शिशिर अवस्थी ने बताया कि हिंदुस्तान लेटेक्स फैमिली प्लानिंग प्रमोशन ट्रस्ट (एचएलएफपीपीटी) द्वारा प्रदेश में कई प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन्नाव में लेदर कटर और जरी-जरदोजी सहित दो ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन दोनों ट्रेडों में कुल 200 युवाओं का नामांकन हुआ है और प्रशिक्षण की अवधि छह माह निर्धारित की गई है। अवस्थी ने जानकारी दी कि इस प्रशिक्षण के लिए 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को शामिल किया गया है, जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत, युवाओं को कानपुर और उन्नाव की विभिन्न फैक्ट्रियों में रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षित युवाओं को न्यूनतम वेतन पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने परिवार की आजीविका में योगदान कर सकें। शिशिर अवस्थी ने यह भी बताया कि जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) और जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान में 200 युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य पूरा होने के बाद भविष्य में नए बैच और अतिरिक्त प्रशिक्षण लक्ष्य मिलने की संभावना है। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के संचालन हेतु परिसर उपलब्ध कराने के लिए स्वास्तिक इंटरनेशनल का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षणार्थी नैन्सी यादव, जो बंथर की निवासी हैं, ने बताया कि वह कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण ले रही हैं। उन्हें यहां सिलाई, कंप्यूटर और कढ़ाई का प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशिक्षण लगभग एक माह से चल रहा है, जबकि इसका औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया। एक अन्य प्रशिक्षणार्थी स्नेहा ने बताया कि अपैरल कोर्स के तहत उन्हें कढ़ाई, बुनाई और सिलाई सिखाई जा रही है। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के बाद वह आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और सिलाई के माध्यम से अपना खर्च स्वयं वहन करने की उम्मीद करती हैं। दोनों प्रशिक्षणार्थियों ने सरकार की योजना की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को हुनर सीखने के ऐसे अवसर लगातार मिलते रहने चाहिए।

कल्याण सिंह की पांचवीं पुण्यतिथि पर उन्नाव भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल पद्म विभूषण कल्याण सिंह की पांचवीं पुण्यतिथि पर उन्नाव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा कार्यालय में सदर विधायक पंकज गुप्ता की अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बाबूजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक पंकज गुप्ता ने कल्याण सिंह के जीवन और संघर्षों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाबूजी ने हमेशा राष्ट्र, समाज और संगठन के हितों को सर्वोपरि रखा। उनका संपूर्ण जीवन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बाबूजी के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया।भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी ने कहा कि कल्याण सिंह का व्यक्तित्व और कृतित्व सभी के लिए मार्गदर्शक है। उनके आदर्शों और विचारों को आत्मसात कर संगठन को मजबूत करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम भेजा गया। ये कार्यकर्ता बाबू कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आधा दर्जन बसों से रवाना हुए। सदर विधायक पंकज गुप्ता और पार्टी पदाधिकारियों ने बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

उन्नाव में मिठाई कारोबारियों पर छापा, 112 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज

उन्नाव में त्योहारों से पहले मिठाई में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने शुक्रवार शाम को औरास थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय प्रियंका सिंह के नेतृत्व में दिनभर चली छापेमारी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। टीम ने तीन स्थानों पर जांच कर 9 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। कार्रवाई के दौरान करीब 1.84 लाख रुपये कीमत की मिठाई, चीनी के घोल, खोया, वनस्पति और दूध नष्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त, 49,720 रुपये कीमत का 112 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज किया गया। बिना लाइसेंस मिठाई निर्माण करते पाए गए दो परिसरों को बंद करा दिया गया। रामपुर गड़उवा निवासी पवन गुप्ता के परिसर में टीम ने खोया, वनस्पति और दूध के नमूने लिए। जांच में यह कारोबार बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के संचालित पाया गया। टीम ने मौके पर 20 किलो खोया और 15 किलो वनस्पति नष्ट कराया, जिसके बाद परिसर को बंद कर दिया गया। इसी गांव में राम विलास के दूसरे परिसर में कार्रवाई के दौरान छेना मिठाई, स्किम्ड मिल्क पाउडर और दूध के नमूने लिए गए। यहां 16 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज किया गया। बिना लाइसेंस मिठाई निर्माण और मानकों के उल्लंघन पर 510 किलो छेना मिठाई, 10 क्विंटल चीनी का घोल और करीब 200 लीटर दूध नष्ट कराया गया। इस कारखाने को भी बंद करा दिया गया। जनता ट्रेडर्स से स्किम्ड मिल्क पाउडर और छेना मिठाई के नमूने लिए गए। यहां 96 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर सीज किया गया, जिसकी कीमत लगभग 43 हजार रुपये बताई गई। इसके अलावा 212 किलो छेना मिठाई नष्ट कराई गई। प्रतिष्ठान संचालक को सुधार के लिए नोटिस जारी किया गया है। पूरी कार्रवाई के दौरान नष्ट कराई गई सामग्री की कुल कीमत 1,84,600 रुपये और सीज सामग्री की कीमत 49,720 रुपये बताई गई है। खाद्य विभाग की टीम ने सभी नौ नमूनों को जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा है। लैब रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

उन्नाव में सड़क हादसों पर लगेगा ब्रेक,

डीएम ने ब्लाइंड कट्स और ओवरलोडिंग पर दिए सख्त निर्देश

उन्नाव में शुक्रवार दोपहर कलेक्ट्रेट के पन्नालाल सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सड़क हादसों पर प्रभावी रोक लगाने, ब्लाइंड कट्स को खत्म करने, साइनेज और स्पीड ब्रेकर लगाने तथा ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में एडीएम, सीएमओ, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, यूपीडा सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य प्रमुख मार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थानों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि एनएच-27 सहित कई मार्गों पर ब्लाइंड कट्स की पहचान की गई है। इन स्थानों को सुरक्षित बनाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर शासन को भेजी जा चुकी है। बजट उपलब्ध होते ही इन स्थानों पर सुधार कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, कई दुर्घटना संभावित स्थानों पर साइनेज, रिफ्लेक्टिव लाइट और रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। सड़क के दोनों ओर ऐसे कई बिंदु चिन्हित किए गए हैं। इन कार्यों का अनुमानित बजट तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर इन कार्यों को जल्द से जल्द शुरू किया जाए।एनएचएआई की टीम को सड़क किनारे निर्धारित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी आवश्यक उपायों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। बैठक में ओवरलोड वाहनों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अप्रैल माह से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ओवरलोड वाहनों पर लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप ओवरलोडिंग में कमी देखी गई है।

16 घंटे बिजली गुल तो भड़का गुस्सा, उन्नाव में लोगों ने सड़क जाम कर लाइनमैन को बनाया बंधक

उन्नाव की मिश्रा कॉलोनी में करीब 16 घंटे से बिजली आपूर्ति बाधित होने से नाराज लोगों का गुस्सा गुरुवार रात फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया और मौके पर पहुंचे लाइनमैन को बंधक बना लिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। घटना का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद बिजली विभाग में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, मिश्रा कॉलोनी में गुरुवार सुबह से बिजली आपूर्ति बाधित थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले ट्रांसफार्मर खराब हो गया था। इसके बाद विभाग की ओर से नया ट्रांसफार्मर भेजा गया, लेकिन वह भी खराब निकला। इससे बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। करीब 16 घंटे तक बिजली न आने से उमस और गर्मी में लोग बेहाल हो गए। रात करीब 11 बजे बड़ी संख्या में लोग सड़क पर एकत्र हो गए। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सड़क जाम कर दी। इसी दौरान मौके पर पहुंचे लाइनमैन को लोगों ने घेर लिया और बंधक बना लिया। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार कई घंटे तक बिजली न आने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया।

शुक्लागंज में नए गंगा पुल का निर्माण अटका, दो माह बाद भी काम ने नहीं पकड़ी रफ्तार

उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी पर प्रस्तावित नए पुल का निर्माण कार्य पिछले दो माह से गति नहीं पकड़ सका है। जून में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद कानपुर छोर से काम रोक दिया गया था, जिसके बाद सेतु निगम ने शुक्लागंज छोर से काम शुरू करने का दावा किया था। शुक्लागंज छोर पर मिश्रा कॉलोनी में पुल निर्माण के रास्ते में आ रहे करीब 40 मकानों को अतिक्रमण की जद में चिह्नित कर मुआवजा वितरित किया गया था। इन मकानों को पोकलैंड मशीनों से ध्वस्त भी कराया गया। अतिक्रमण हटने के बाद उम्मीद थी कि निर्माण कार्य में तेजी आएगी, लेकिन लगभग दो माह बाद भी मौके पर काम शुरू नहीं हो सका है। फिलहाल, निर्माण स्थल पर केवल मलबा हटाने का काम चल रहा है। नए गंगा पुल के लिए शुक्लागंज छोर पर चिन्हित 40 मकानों के स्वामियों को चेक के माध्यम से मुआवजा दिया गया था। इसके बाद दो सप्ताह से अधिक समय तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाकर पोकलैंड मशीनों से मकानों को ध्वस्त कर रास्ता खाली कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अतिक्रमण हटाए जाने के बाद काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पूरी जगह निर्माण के लिए तैयार नहीं हो सकी है। जगह-जगह मलबा और भवनों के अवशेष पड़े होने से भी निर्माण कार्य शुरू होने में देरी हो रही है। लोगों ने उम्मीद जताई थी कि जिस तेजी से अतिक्रमण हटाया गया था, उसी तरह निर्माण कार्य भी शुरू होगा। इससे पहले, जून में गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कानपुर छोर से चल रहा नए पुल का निर्माण कार्य रोकना पड़ा था। नदी का पानी बढ़ने से निर्माण कार्य में लगी मशीनों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया था।

UP में Ola-Uber और डिलीवरी कंपनियों पर सख्ती नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू

उत्तर प्रदेश में एप आधारित कैब, डिलीवरी और कूरियर सेवाओं के लिए नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसके तहत लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।नई व्यवस्था में किराया, यात्रियों की सुरक्षा, ड्राइवरों के सत्यापन और बीमा से जुड़े नियम तय किए गए हैं, जबकि पीक टाइम में किराया 50% से ज्यादा बढ़ाने पर रोक रहेगी।

उत्तर प्रदेश में एप आधारित कैब और डिलीवरी सेवाओं को लेकर अब नियम पहले से ज्यादा सख्त और व्यवस्थित हो गए हैं। प्रदेश में नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू होने के साथ Ola-Uber जैसी कैब सेवाओं के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी डिलीवरी और कूरियर कंपनियों के लिए भी लाइसेंस और सुरक्षा से जुड़े नियम तय किए गए हैं। सरकार का फोकस यात्रियों को सुरक्षित और तय व्यवस्था के तहत सेवा देने के साथ-साथ ड्राइवरों के हितों को भी मजबूत करने पर है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में काम कर रहे सभी एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने अपना पोर्टल ऑनलाइन कर दिया है। कोई नया एग्रीगेटर बिना लाइसेंस लिए सेवा शुरू नहीं कर सकेगा। आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन रखी गई है। नई पॉलिसी में सबसे अहम प्रावधान कैब के किराए को लेकर है। एग्रीगेटर तय बेस फेयर से अधिकतम 50 फीसदी तक ही किराया बढ़ा सकेंगे। यानी पीक टाइम या ज्यादा मांग के नाम पर किराए में मनमानी बढ़ोतरी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा अगर बुकिंग के बाद ड्राइवर तय समय तक यात्री को लेने नहीं पहुंचता है तो 100 रुपये की पेनाल्टी का प्रावधान किया गया है। यह राशि यात्री को अगली ट्रिप में लाभ के रूप में दी जाएगी।नई नीति में यात्रियों की सुरक्षा को खास महत्व दिया गया है। खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए पंजीकृत वाहनों में लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था होगी। ड्राइवरों का चरित्र सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही उनके मनोवैज्ञानिक परीक्षण और समय-समय पर रीफ्रेशर ट्रेनिंग का भी प्रावधान रखा गया है। यात्रियों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान कराने के लिए प्रत्येक एग्रीगेटर को ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना होगा। पॉलिसी में केवल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि ड्राइवरों के कल्याण की भी व्यवस्था की गई है। एग्रीगेटर को प्रत्येक चालक के लिए पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस उपलब्ध कराना होगा। यात्रियों के लिए भी बीमा की व्यवस्था की गई है। प्रदूषण कम करने के लिए एनसीआर क्षेत्र में वाहनों की निगरानी की व्यवस्था भी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। एग्रीगेटर की फ्लीट में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है। इससे आने वाले समय में एप आधारित परिवहन सेवाओं में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत एग्रीगेटर को आवेदन के लिए 25 हजार रुपये फीस देनी होगी, जबकि लाइसेंस फीस पांच लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा फ्लीट के आकार के आधार पर सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। 100 बसों या 1000 अन्य मोटर वाहनों वाली फ्लीट के लिए 10 लाख रुपये, 1000 बसों या 10 हजार अन्य मोटर वाहनों के लिए 25 लाख रुपये और इससे अधिक बड़ी फ्लीट के लिए 50 लाख रुपये की सिक्योरिटी मनी का प्रावधान है। यह नीति सिर्फ कैब सेवाओं तक सीमित नहीं है। डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए सामान, पैकेज या पार्सल की डिलीवरी से जुड़ी सेवाओं को भी इसके तहत पंजीकरण कराना होगा। कुल मिलाकर नई एग्रीगेटर पॉलिसी का मकसद एप आधारित परिवहन और डिलीवरी सेवाओं को एक तय नियामक ढांचे में लाना है। इससे यात्रियों के लिए किराए और सुरक्षा से जुड़े नियम स्पष्ट होंगे, वहीं ड्राइवरों और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारियां भी तय होंगी।

गन्ने के खेत में घास काट रहे बेटे पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया

यूपी के लखीमपुर खीरी स्थित बरबर क्षेत्र में गलरई भट्टे के समीप शुक्रवार को गन्ने के खेत में घास काट रहे किसान पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से गांव ककराही निवासी किसान केपी जोशी (22) पुत्र शिवकरण गंभीर रूप से घायल हो गया। बेटे की चीख-पुकार सुनकर पिता शिवकरण लाल बिना अपनी जान की परवाह किए बाघ का सामना करते हुए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसान भी मौके की ओर दौड़ पड़े। कई किसानों के एक साथ शोर मचाने पर बाघ घायल किसान को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया। बाघ के चंगुल से निकलने के बाद केपी जोशी लड़खड़ाते हुए खेत से बाहर आए और बेहोश हो गए। परिजनों ने तत्काल एंबुलेंस की मदद से घायल किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी पहुंचाया। वहां स्थित नाजुक देख डॉक्टरों ने जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। बाघ के हमले के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मौके पर रेंजर निर्भय प्रताप शाही, डीएफओ साउथ तापस मिहिर पहुंचे। वन रेंजर निर्भय प्रताप शाही ने बताया कि हमला करने वाला वन्यजीव तेंदुआ लग रहा है। कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे की नजर में आने पर सही बताया जा सकता है।

कानपुर में IT कर्मचारी ने फांसी लगाकर दी जान कथित सुसाइड नोट में बहन पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप

उत्तर प्रदेश के कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के कृष्णापुरम में शुक्रवार सुबह एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रवि दीक्षित के रूप में हुई है, जो आईटी सेक्टर में काम करता था और फिलहाल वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मामला पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस को एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने अपनी बहन पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार शुक्रवार सुबह रवि घर के बाहर बने कमरे में गए थे। कुछ देर बाद जब परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चकेरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके से मिले कथित सुसाइड नोट को भी कब्जे में लिया है। नोट में लगाए गए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सुसाइड नोट और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक की पत्नी ज्योति दीक्षित के मुताबिक रवि की बड़ी बहन छवि मिश्रा पिछले काफी समय से संपत्ति, ज्वेलरी और खेती-बाड़ी में बंटवारे की मांग कर रही थीं। पत्नी का आरोप है कि इसी पारिवारिक विवाद को लेकर रवि पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और करीब एक साल से वह मानसिक तनाव में थे। हालांकि, पुलिस फिलहाल इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सुसाइड नोट में लिखी बातों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। रवि की शादी करीब 10 साल पहले ज्योति से हुई थी। दंपती का सात साल का एक बेटा है।

वंदे मातरम् पर सियासत ठीक नहीं बेरोजगारी और बाढ़ जैसे मुद्दों पर ध्यान दें सरकारें

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि वंदे मातरम् पर जारी सियासत ठीक नहीं है और केन्द्र व सभी राज्य सरकारों तथा राजनैतिक दलों को अति-महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देना चाहिये। मायावती ने शुक्रवार को 'एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, "देश में वंदे मातरम् को पूरा गाना है या शुरुआती दो अंतरे गाने हैं या नहीं गाना है, इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, वह ठीक नहीं है।" उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् गायन को लेकर हाल में संसद में जो कानून पास किया गया है वह बदलाव का कोई पहला मामला नहीं है। बसपा प्रमुख ने कहा कि " केंद्र और राज्यों में सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ या फायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसा करती रहती हैं, यानी एक-दूसरे के बनाए कानूनों को बदलती रहती हैं।" मायावती ने कहा कि इस समय देश और जनहित के कई अहम मुद्दे हैं।

उन्होंने कहा, " बेरोजगार युवाओं, छात्र-छात्राओं जेन-जी और स्कूली बच्चों जेन-अल्फा के मुद्दे तथा देश के कुछ हिस्सों में आई भयंकर बाढ़ से हो रही जान-माल की हानि जैसे अनेक अति-महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और सभी राज्य सरकारों के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों को समुचित ध्यान देना चाहिए।